National Conference on Recent Trends in Engineering, Science, Humanities and Management (NCRTESHM – 2023)
29th January, 2023, West Bengal, India.

CERTIFICATE NO : NCRTESHM /2023/C0123159

हिजरा की शिक्षा और अधिकारिता के लिए शैक्षिक पहल का अध्ययन

SOHAN KUMAR YADAV

Research Scholar, Department of Education,
Dr. A.P.J. Abdul Kalam University, Indore, M.P.

सारांश

सरकार ने लड़कों और लड़कियों के बीच लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई)–1986, कार्य योजना (पीओए)–1992 सर्व शिक्षा अभियान–2001 शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 आदि जैसी कई शैक्षिक पहल की हैं। शैक्षिक नामांकन और ड्रॉप आउट में। हालांकि, थर्ड जेंडर के शैक्षिक उत्थान के लिए ऐसी कोई नीति लागू नहीं की गई है। सितंबर 1994 में, भारत के चुनाव आयोग ने निर्देश दिया कि नामांकन के समय उनके बयान के आधार पर टीजी / हिजड़ों को मतदाता सूची में पुरुष या महिला के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। 2013 में पहली बार चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र पर श्अन्यश विकल्प पेश करके चुनावी प्रक्रिया में टीजी/हिजड़ों को मान्यता दी, लेकिन ट्रांसजेंडर इससे खुश नहीं हैं, उन्होंने 'अन्य' के बजाय 'ट्रांसजेंडर' विकल्प की मांग की। पुरुष या महिला की पहचान की परवाह किए बिना व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत शिक्षण संस्थानों में तीसरे लिंग के बच्चों को शामिल करने की सलाह दी। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नालसा के फैसले के चार साल बाद भी, ट्रांसजेंडर लोग अभी भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हर रोज लोगों, पुलिस और अपराधियों से भारी हिंसा का सामना कर रहे हैं। 31 दिसंबर 2014 को 43,602 ट्रांसजेंडरों के पास उनके नाम का विशिष्ट पहचान पत्र (यूआईडी) नंबर था। यह भारत की कुल ट्रांसजेंडर आबादी का केवल 9% अनुपात है। 2005 में भारतीय पासपोर्ट

में तीसरे लिंग के विकल्प के लिए (हिजड़ा) का प्रतीक था, लेकिन मार्च 2015 में नालसा के फैसले के बाद, ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन फॉर्म में लिंग श्रेणी में 'ट्रांसजेंडर' का विकल्प भी था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत जमा किए गए राशन कार्ड के लिए आवेदन फॉर्म में लिंग श्रेणी में 'अन्य' विकल्प था जिसमें एक ट्रांसजेंडर शामिल होगा।